भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5320

उत्तर देने की तारीख : 03.04.2025

एमएसएमई क्षेत्र में कार्यबल के कौशल में सुधार

5320. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में कार्यबल, विशेषकर महिलाओं और युवा उद्यमियों के कौशल में सुधार के लिए क्या पहल की जी रही है; और

(ख) एमएसएमई क्षेत्र को उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने और उनकी उत्पादकता में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विभिन्न क्षेत्रों में उभरते हुए और पारंपरिक क्षेत्रों के कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए एक कौशल तंत्र का विकास किया है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इस मंत्रालय के अंतर्गत संस्थानों के नेटवर्क अर्थात खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कॅयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), राष्ट्रीय एमएसएमई संस्थान (एनआई-एमएसएमई) और एमएसएमई-प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

मंत्रालय मौजूदा और संभावित उद्यमियों के लिए उनकी क्षमता निर्माण हेतु अनेक कौशल विकास कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उद्योग की मांग के अनुरूप होते हैं, तथा एमएसएमई इको-सिस्टम के बदलते परिदृश्य और भारत में इसकी वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप एमएसएमई क्षेत्र में कुशल कार्यबल की आवश्यकता के अंतर को पूरा करने में प्रशस्त होते हैं।

मंत्रालय महत्वाकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों के उद्यमशीलता कौशल के संवर्धन के लिए उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना को भी लागू कर रहा है, जिसमें महिलाओं के साथ-साथ युवा उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये ईएसडीपी कार्यक्रम विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रौद्योगिकी केंद्रों और आईआईटी/आईआईएम/एनआईटी/सीएसआईआर/ आईसीएआर, कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों जैसे अन्य प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

पिछले 3 वर्षों (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक) में ईएसडीपी योजना के तहत दादरा और नगर हवेली में लाभार्थियों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	वर्ष	आयोजित कार्यक्रम	कुल लाभार्थी	लाभार्थी	
				पुरुष	महिला
1	2022-23	8	608	313	295
2	2023-24	12	467	147	320
3	2024-25	20	1163	583	580
कुल		**40**	**2238**	**1043**	**1195**

(ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने एमएसएमई को उन्नत तकनीक अपनाने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, अर्थात:-

एमएसएमई चैंपियंस योजनाएं: इस व्यापक पहल का उद्देश्य एमएसएमई को विभिन्न पहलुओं में सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन, उद्यमों का चयन करना उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अवशिष्ट को कम करना, उत्पादकता में सुधार करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और उनकी राष्ट्रीय व वैश्विक पहुंच को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

इसमें तीन घटक शामिल हैं अर्थात,

i) एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन योजना (दिनांक 28.04.2022 को शुरू की गई)
ii) एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना (दिनांक 10.03.2023 को शुरू की गई)
iii) एमएसएमई-इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) योजना (दिनांक 10.3.2022 को शुरू की गई)।

एमएसएमई सस्टेनेबल (जेड) प्रमाणन योजना घटक के अंतर्गत, सभी जेड प्रमाणित एमएसएमई के लिए जीरो इफेक्ट सोल्यूशंस हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन में 3 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है।

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 1967 और 1999 के बीच 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी), जिन्हें पहले टूल रूम (10) और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (8) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना की है ताकि उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई को उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करके, प्रौद्योगिकी विकास में जनशक्ति को कुशल बनाकर तथा तकनीकी और व्यावसायिक परामर्शी सहायता प्रदान करके उन्हें सहायता प्रदान की जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय पूरे देश में 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और 100 विस्तार केंद्रों (ईसी) की स्थापना के लिए 'नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना' नामक एक योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है, ताकि प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन तथा परामर्शी सेवाओं के लिए एमएसएमई की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनका समाधान प्रदान कर टीसी के नेटवर्क की भौगोलिक पहुंच को बढ़ाया जा सके।

******